Publication	The Times of India	Language	English
Edition	New Delhi	Journalist	TNN
Date	09/03/2024	Page no	16
CCM	43.74		

Database of 8L cooperatives to help in framing policies: Shah

Database of 8L cooperatives to help in framing policies: Shah

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Union home and cooperation minister Amit Shah on Friday launched National Cooperative Database that maps details of about 8 lakh cooperatives, with a collective membership of over 30 crore, in country. It is a web-based digital dashboard wherein data of all cooperative societies, including national/state federations, have been captured.

Shah said that the database will help in promoting expansion of the cooperative sector and will act as an invaluable resource for policymakers, researchers and stakeholders.

Data shows that housing sector has the highest number of cooperatives (1,91,753) in country followed by dairy (1,41,885), primary agricultural credit societies (98,237), credit & thrift (80,032) and labour (44,564).

Noting that data works to guide development in the right direction and will be highly effective in analysing gaps, Shah said, "We are experiencing a new trend in this era — data governance, proactive governance, and anticipatory governance. The synergy of these three leads to establishment of a new development model."

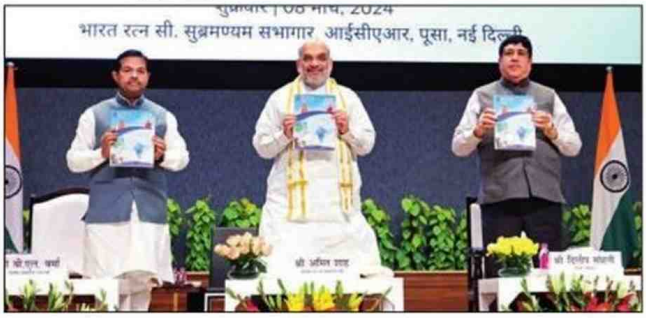

Amit Shah releases 'National Cooperative Database 2023' in New Delhi on Friday. Union minister of state for cooperation BL Verma and IFFCO chairman Dileep Sanghani were also present on the occasion

He said the database has the potential to connect primary agricultural credit societies (PACS) to apex (bigger) cooperatives, villages to cities, mandis to the global market, and state databases to international databases. With the help of this platform, all information about registered cooperative societies across country will be available at the click of a button, Shah added.

He further said all PACS in country have been computerised in past two years, and all states in country have risen above partisan politics and accepted model bylaws, paving way for expansion of PACS. It has already been decided that there will be a PACS in every village in country by 2027, he added.

Shah on the occasion assured authenticity of the data in National Cooperative Database, and said a comprehensive scientific system will ensure it is regularly updated.

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	The Hindu Business Line	Language	English
Edition	Mumbai	Journalist	Bureau
Date	09/03/2024	Page no	9
CCM	49.77		

Shah launches co-op database for policy making

Shah launches co-op database for policy making

Our Bureau
New Delhi

Cooperation Minister Amit Shah on Friday launched the National Cooperative Database and stressed that it would help in policy making. Pointing out that as many as 25 per cent of gram panchayats do not have a single PACS, Shah blamed imbalanced growth led to the decline in cooperative sector after 1975.

"After the separate cooperation ministry was carved out of the agriculture ministry (two years back), some people had deliberated on the reasons for the downfall of the cooperative sector. It was found that the growth in cooperative sector was stagnant after 1965 and started declining from 1975 onwards," Shah said.

STRENGTHENING COOPERATIVES. Union Minister for Home Affairs and Cooperation Amit Shah with Union MoS for Cooperation BL Verma and NCUI Secretary Dileep Sanghani during the inauguration of the National Cooperative Database PTI

IMBALANCE GROWTH

Further, he pointed out that several district cooperative banks had to wind up, many PACS went bankrupt in last many years. According to Shah, there was imbalanced growth, not only geographically, but also there was imbalance growth across various segments in the cooperative structure itself. "There was imbalance in its functionality and also community-based development," he added.

The minister also said that 75 per cent of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) are affiliated with any district cooperative bank while 25 per cent remaining are still to be connected. The National Database has collected information of about 8 lakh cooperatives, majority of them PACS or primary societies, with collective membership of nearly 30 crore.

Shah said that the database would help in promoting the expansion of the cooperative sector. "Such valuable information is there that if one takes a deep inside, one will come come out with a pearl," he said.

PHASED MANNER

The data of cooperatives was collected on the National Cooperative Database in a phased manner from the various stakeholders. In the first phase, mapping of about 2.64 lakh primary cooperative societies of three sectors — PACS, Dairy and Fisheries — was completed.

In the second phase, data of various National Federations, State Federations, State cooperative banks (StCB), District Central Cooperative Banks (DCCBs), Urban Cooperative Banks (UCBs), State Cooperative Agriculture and Rural Development Bank (SCARDB), Primary Cooperative Agriculture and Rural Development Bank (PCARDB), Cooperative Sugar Mills, District Unions and Multi State Cooperative Societies (MSCS) were collected. In the third phase, data of more than 5.3 lakh primary cooperative societies including PACS was mapped from all the remaining other sectors through the office of different state government agencies including from district registrars.

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from
SAMVAD

Publication	Amar Ujala	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	09/03/2024	Page no	15
CCM	86.90		

National database will show the direction of development of cooperative sector like a compass

सहकारिता क्षेत्र के विकास को कंपास की तरह दिशा दिखाएगा राष्ट्रीय डाटाबेस

सहकारिता मंत्री शाह ने पोर्टल का किया लोकार्पण, कहा-एक क्लिक पर मिलेगी हर जानकारी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय डाटाबेस सहकारिता क्षेत्र के विकास में मददगार साबित होगा। यह सहकारिता क्षेत्र के विकास को कंपास की तरह दिशा दिखाएगा। उन्होंने कहा, इससे सहकारिता क्षेत्र का विस्तार, विकास और लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित होगी। शाह शुक्रवार को सहकारी डाटाबेस पोर्टल के उद्घाटन और 'राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस 2023 : एक रिपोर्ट' के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे।

शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र के विस्तार और उसकी मजबूती के लिए 75 साल बाद पहली बार सहकारिता डाटाबेस का लोकार्पण हो रहा है। राष्ट्रीय डाटाबेस से सहकारिता की हर एक जानकारी अब एक क्लिक पर मिलेगी। देशभर में कहां सहकारी समितियां कम हैं, उस गैप की पहचान कर सहकारिता के विस्तार में राष्ट्रीय डाटाबेस मददगार साबित होगा। शाह ने कहा, हजारों लोगों की दो साल की मेहनत के बाद आज हमें ये सफलता मिली है। 60 के दशक के बाद ये जरूरत महसूस की गई कि एक राष्ट्रीय नीति के तहत हर राज्य के सहकारिता आंदोलन के बीच समन्वय हो। सहकारिता मंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) कंप्यूटरीकृत हो गई हैं और सभी राज्य भी कम्प्यूटरीकृत हो गए है और पैक्स मॉडल उपनियमों को स्वीकार किया है। कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित करीब 1400 लोगों ने शिरकत की।

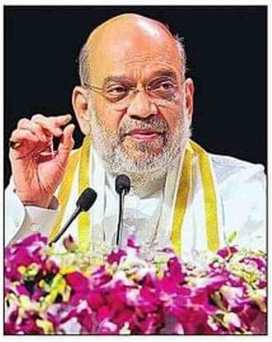

सहकारी डाटाबेस पोर्टल के उद्घाटन के बाद संबोधित करते अमित शाह। एजेंसी

10 साल में गरीबी रेखा से ऊपर हुए 25 करोड़ लोग

शाह ने कहा, पीएम मोदी ने देश के ग्रामीण अर्थतंत्र और जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने और पिछले 10 साल में देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है। करोड़ों लोगों को देश के अर्थतंत्र और विकास के साथ जोड़ने का काम सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से हो रहा है। अर्थशास्त्री अब आश्चर्यचकित हैं। लगभग 60 करोड़ लोगों ने गैस सिलिंडर, भोजन, घर, दवाएं जैसी बुनियादी सुविधाएं हासिल कीं। उन्होंने कहा कि डाटा, विकास को सही दिशा देने का काम करता है और गैप का विश्लेषण करने में ये बहुत कारगर सिद्ध होगा।

पीएससीएस को 20 अलग-अलग गतिविधियों से जोड़ा

सहकारिता मंत्री ने कहा, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) अब मुनाफा कमा रही हैं। हमने पीएससीएस को 20 अलग-अलग गतिविधियों से जोड़ा। आज, वे एक गरीब किसान के लिए रेलवे या एयरलाइन टिकट बुक करवा रहे हैं, वे 'बैंक मित्र' के रूप में काम कर रहे हैं। पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण ने उनके विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।

आठ लाख से अधिक समितियां पंजीकृत, 30 करोड़ से अधिक लोग जुड़े

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में तीन चरणों में हुए काम का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, पहले चरण में, तीन क्षेत्रों यानी प्राथमिक कृषि ऋण समिति, डेयरी और मत्स्यकी की लगभग 2.64 लाख समितियों की मैपिंग पूरी की गई। दूसरे चरण में विभिन्न राष्ट्रीय संघों, राज्य संघों, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, सहकारी चीनी मिलों, जिला यूनियनों और बहुराज्य सहकारी समितियों के आंकड़े एकत्रित/मैप किए गए। तीसरे चरण में अन्य बाकी क्षेत्रों में सभी 8 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों के डेटा की मैपिंग की गई। देश में 8 लाख से अधिक समितियां पंजीकृत हैं और 30 करोड़ से अधिक नागरिक इनसे जुड़े हैं।

ग्रामीण समाज का होगा समग्र कल्याण

केंद्रीय मंत्री ने कहा, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय संघों और हितधारकों के साथ सहयोग करते हुए, सहकारी-केंद्रित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस विकसित किया गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों का विकास आर्थिक, सामाजिक और सामुदायिक चुनौतियों का समाधान करने, व्यक्तियों को सशक्त बनाने, गरीबी को कम करने और ग्रामीण समाज के समग्र कल्याण में योगदान देने का वादा करता है।

सवा सौ साल चलेगी ये मजबूत इमारत

शाह ने कहा, आज एक नींव डाली गई है और आने वाले वर्षों में इस नींव पर अगले सवा सौ साल तक चलने वाली एक मजबूत सहकारिता की इमारत खड़ी होगी। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय डाटाबेस अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बनाया गया एक डायनेमिक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है और इसकी मदद से देशभर की पंजीकृत सहकारी समितियों की सारी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा, सहकारिता डेटाबेस, नीति निर्धारकों, शोधकर्ताओं और अन्य साझेदारों के लिए अमूल्य संसाधन का काम करेगा।

- सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि इस डाटाबेस पर सत्यापित डाटा ही नियमित रूप से अपलोड हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 1975 के बाद देश में सहकारिता आंदोलन की गति बहुत कम होती गई क्योंकि हमारे यहां भौगोलिक दृष्टिकोण से असंतुलित विकास हुआ। तमाम समस्याओं का टूल्स के साथ समाधान डाटाबेस में डाला गया है। शाह ने कहा कि आज हजारों लोगों, संघों और राज्यों ने मिलकर एक भागीरथ काम को अंजाम दिया है।

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Dainik Bhaskar	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	09/03/2024	Page no	2
CCM	24.33		

Home Minister Shah launched the National Cooperative Database Portal

गृह मंत्री शाह ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल का लोकार्पण किया

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का लोकार्पण और राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023 एक रिपोर्ट का विमोचन किया। इस मौके पर शाह ने कहा आज सहकारिता क्षेत्र, इसके विस्तार और इसे मजबूत करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है, जब 75 साल बाद पहली बार सहकारिता डेटाबेस का लोकार्पण हो रहा है। 60 के दशक के बाद ये जरूरत महसूस की गई कि एक राष्ट्रीय नीति के तहत हर राज्य के सहकारिता आंदोलन के बीच समन्वय हो। पीएम मोदी के फैसले उसे अंजाम तक पहुंचाया और सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। शाह ने कहा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में तीन चरणों में काम हुआ है। पहले चरण में तीन क्षेत्रों प्राथमिक कृषि ऋण समिति, डेयरी

और मात्स्यिकी की लगभग 2.64 लाख समितियों की मैपिंग पूरी की गई। दूसरे चरण में राष्ट्रीय संघों, राज्य संघों सहित कई सहकारी समितियों के आंकड़े एकत्रित/मैप किए गए। तीसरे चरण में अन्य बाकी क्षेत्रों में सभी 8 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों के डेटा को मैप किया गया। उन्होंने कहा इसके बाद हमें पता चला कि देश में 8 लाख से अधिक समितियां पंजीकृत हैं और 30 करोड़ से अधिक नागरिक इनसे जुड़े हैं।

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Dainik Jagran	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	09/03/2024	Page no	12
CCM	65.68		

Complete horoscope of cooperation will be available on one click

एक क्लिक पर निकलेगी सहकारिता की पूरी कुंडली

अमित शाह ने किया राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस पोर्टल का लोकार्पण, समितियों के विकास में मिलेगी मदद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: हजारों लोगों के दो वर्षों के कठिन एवं लगातार परिश्रम के बाद सहकारिता क्षेत्र की गतिविधियों की सारी जानकारियों के लिए डिजिटल आधारित डाटाबेस तैयार किया गया है। इसके माध्यम से सहकारिता क्षेत्र की सारी सूचनाएं एवं गतिविधियां एक क्लिक पर ही आसानी से मिल जाएंगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस पोर्टल का लोकार्पण और 'राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस-2023: एक रिपोर्ट' का विमोचन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वह साहसिक फैसले लेते हैं और उन्हें अंजाम तक भी पहुंचाते हैं।

अमित शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 75 वर्ष बाद इतना बड़ा काम हुआ है। यह डाटाबेस सहकारिता के विकास, विस्तार और आपूर्ति को कंपास की तरह दिशा दिखाएगा। जिन क्षेत्रों में सहकारी समितियां कम या कमजोर हैं, उसकी पहचान कर विस्तार में मदद करेगा। पोर्टल के जरिये छोटी सहकारी संस्थाएं अपने विस्तार के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगी। इसे अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर बनाया गया है।

इसमें गांवों को शहरों से, मंडियों को ग्लोबल मार्केट से और राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय संपर्क से जोड़ने की संभावना मौजूद है। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने साहसिक फैसला लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाते हुए अलग मंत्रालय बनाया। सभी पैक्स का कंप्यूटरीकरण हो गया है। तय किया गया है कि 2027 से पहले देश की हर पंचायत में एक पैक्स होगा। इसके बाद की समस्याओं के समाधान के लिए डाटाबेस का विचार आया।

सहकारिता में कंप्यूटरीकरण से जुड़े कई नवाचार किए

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में कंप्यूटरीकरण से जुड़े कई नवाचार किए हैं।

डाटाबेस देश की सहकारिता गतिविधियों की कुंडली है। आंकड़ों की प्रामाणिकता और उन्हें अपडेट करने के लिए वैज्ञानिक व्यवस्था की गई है। नीति निर्धारकों, शोधकर्ताओं एवं स्टेकहोल्डर के लिए अमूल्य संसाधन का काम करेगा। अमित शाह ने डाटाबेस को नींव बताया, जिसपर अगले सवा सौ साल तक चलने वाली एक मजबूत सहकारिता की इमारत खड़ी होगी।

- बोले-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साहसिक फैसले लेते हैं और उन्हें अंजाम तक पहुंचाते हैं
- **2027** से पहले हर पंचायत में एक पैक्स होगा, किसानों को होगी सुविधा

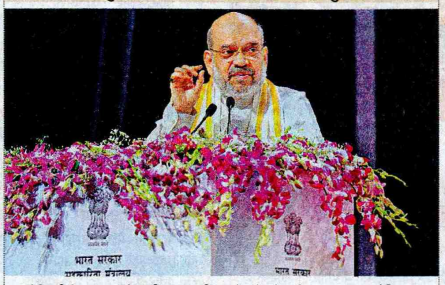

नई दिल्ली में शुक्रवार को राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस के लोकार्पण अवसर पर संबोधित करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह● प्रेट

डाटाबेस में तीन चरणों में काम हुआ

अमित शाह ने कहा कि डाटाबेस में तीन चरणों में काम हुआ है। पहले चरण में तीन क्षेत्रों यानी प्राथमिक कृषि ऋण समिति, डेयरी और मत्सियकी की लगभग 2.64 लाख समितियों की मैपिंग पूरी की गई। दूसरे चरण में विभिन्न राष्ट्रीय संघों, राज्यों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला सहकारी एवं शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, सहकारी चीनी मिलों, जिला यूनियनों और बहुराज्य सहकारी समितियों के आंकड़े एकत्र किए गए हैं। तीसरे चरण में सभी आठ लाख प्राथमिक सहकारी समितियों के डाटा की मैपिंग की गई।

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Hindustan	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	09/03/2024	Page no	8
CCM	56.28		

Database will give impetus to cooperation: Shah

गृह मंत्री ने कहा, एक क्लिक पर पूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी

डाटाबेस से सहकारिता को गति मिलेगी : शाह

उम्मीद

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस की शुरुआत करते हुए कहा कि डाटाबेस की मदद से सहकारिता क्षेत्र को गति मिलेगी। इसके विस्तार में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 75 साल बाद पहली बार सहकारिता डाटाबेस शुरू किया जा रहा है।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहसिक फैसला लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाते हुए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता को गति देने में समस्या आई, हमें ये पता नहीं था कि परेशानी कहां है और तब इस डेटाबेस का विचार आया। जिसके द्वारा परेशानी की पहचान कर विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डाटाबेस की पेशकश, सहकारी क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा।

एक क्लिक पर पूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी : केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा, इस को-ऑपरेटिव डाटाबेस से सहकारिता का विस्तार, डिजिटल माध्यम से डेवलपमेंट और डाटाबेस से डिलीवरी का काम होगा। डाटा, विकास को सही दिशा देने का काम करता है। यह समस्या का अध्ययन करने में बहुत कारगर सिद्ध होगा।

नई दिल्ली में शुक्रवार को राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस की शुरुआत के मौके पर कार्यक्रम में संबोधित करते सहकारिता मंत्री अमित शाह ●एएनआई

देश की हर पंचायत में एक पैक्स होगा

शाह ने कहा कि अब तक 20 नई गतिविधियों को पैक्स के साथ जोड़ा है, जिससे पैक्स मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पैक्स के कम्प्यूटरीकरण से इनके विकास की कई संभावनाएं खुलीं। यह तय किया गया कि 2027 से पहले देश की हर पंचायत में एक पैक्स होगा। देश में आठ लाख से अधिक समितियां पंजीकृत हैं। 30 करोड़ से अधिक नागरिक इनसे जुड़े हैं।

क्या है डाटाबेस

राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस एक वेब-आधारित डिजिटल डैशबोर्ड है, जिसमें राष्ट्रीय एवं राज्य संघों सहित सहकारी समितियों के आंकड़ों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय डाटाबेस (आंकड़ों की सूची) के तहत देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली 29 करोड़ से अधिक की सामूहिक सदस्यता वाली आठ लाख सहकारी समितियों के बारे में जानकारी एकत्र की गई है।

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from
SAMVAD

Publication	Jansatta	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	09/03/2024	Page no	16
CCM	32.56		

Arrangements for village development will be online before 2027

'गांव के विकास के लिए 2027 से पहले आनलाइन होगी व्यवस्था'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 मार्च।

केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह सरकार लगातार प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी (पीएसीएस- पैक्स) के लिए आन लाइन व्यवस्था को तेजी से लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 20 नई गतिविधियों को पैक्स के साथ जोड़ा है, जिससे पैक्स मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पैक्स के कम्प्यूटरीकरण से ग्रामीण विकास की कई संभावनाएं खुलीं और ये तय किया गया कि 2027 से पहले देश की हर पंचायत में एक पैक्स होगा।

अमित शाह ने कहा कि इस निर्णय के बाद समस्या आई कि हमें ये पता नहीं था कि अंतर (गैप) कहां है। इसके बाद गैप की पहचान कर विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डेटाबेस

शाह ने कहा कि देश के ग्रामीण अर्थतंत्र में परिवर्तन लाने और देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया गया है।

सहकारिता क्षेत्र के विकास को दिशा दिखाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में देश के सभी पैक्स कम्प्यूटरीकृत हो गए हैं, उनके कारोबार में वृद्धि करने के लिए एक समान उप कानून सभी राज्यों ने स्वीकार किए हैं और आज सभी पैक्स विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं। वे नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

अमित शाह ने कहा कि 60 के दशक के बाद ये जरूरत महसूस की गई कि एक राष्ट्रीय नीति के तहत हर राज्य के सहकारिता आंदोलन के बीच समन्वय हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने साहसिक फैसला लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाया।

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from
SAMVAD

Publication	Rajasthan Patrika	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Anurag Mishra
Date	09/03/2024	Page no	2
CCM	67.61		

PM Modi takes bold decisions and implements them: Shah

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल का लोकार्पण और 'राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023 : एक रिपोर्ट' का विमोचन

पीएम मोदी साहसिक फैसले लेते हैं, उन्हें अंजाम तक पहुंचाते हैं : शाह

पत्रिका अनुराग मिश्रा patrika.com

नई दिल्ली. आज सहकारिता क्षेत्र, इसके विस्तार और इसे मजबूत करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है जब 75 साल बाद पहली बार सहकारिता डेटाबेस का लोकार्पण हो रहा है। सहकारिता क्षेत्र के विस्तार और उसे गति प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का लोकार्पण और 'राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023: एक रिपोर्ट' का विमोचन कार्यक्रम में ये बातें कही।

शाह ने कहा कि हजारों लोगों के दो साल तक किए गए परिश्रम के बाद आज हमें ये सफलता मिली है। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि 60 के दशक के बाद ये जरूरत महसूस की गई कि एक राष्ट्रीय नीति के तहत हर राज्य के सहकारिता आंदोलन के बीच समन्वय हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साहसिक फैसला लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाते हुए केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में देश के सभी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी कम्प्यूटराइज्ड हो गए हैं, उनके कारोबार में वृद्धि करने के लिए कॉमन बायलॉज सभी राज्यों ने स्वीकार किए हैं और आज सभी पैक्स विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं।

इस कोऑपरेटिव डेटाबेस से सहकारिता का विस्तार, डिजिटल माध्यम से डेवलपमेंट और डेटाबेस से डिलिवरी का काम होगा। उन्होंने कहा कि डेटा, डेवलपमेंट को सही दिशा देने का काम करता है और गैप का एनालिसिस करने में ये बहुत कारगर सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि इस काल में हम एक नए ट्रेंड का अनुभव कर रहे हैं- डेटा गवर्नेंस, प्रोएक्टिव गवर्नेंस और एंटिसिपेटरी गवर्नेंस और इन तीनों के सामंजस्य से विकास का एक नया मॉडल खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि इसके बाद हमें पता चला कि देश में 8 लाख से अधिक समितिया पंजीकृत हैं और 30 करोड़ से अधिक नागरिक इनसे जुड़े हैं।

इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री बी एल वर्मा और डॉ. आशीष कुमार भूटानी, सचिव, सहकारिता मंत्रालय सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

2027 से पहले हर पंचायत में एक पैक्स होगा

शाह ने कहा कि हमने 20 नई गतिविधियों को पैक्स के साथ जोड़ा है जिससे पैक्स मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पैक्स के कम्प्यूटरीकरण से इनके विकास की कई संभावनाएं खुलीं और ये तय किया गया कि 2027 से पहले देश की हर पंचायत में एक पैक्स होगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के ग्रामीण अर्थतंत्र और जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने और पिछले 10 साल में देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है।

तीन चरणों में काम हुआ

शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में तीन चरणों में काम हुआ है। पहले चरण में, तीन क्षेत्रों यानी प्राथमिक कृषि ऋण समिति, डेयरी और मत्स्यिकी की लगभग 2.64 लाख समितियों की मैपिंग पूरी की गई। दूसरे चरण में विभिन्न राष्ट्रीय संघों, राज्य संघों, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, सहकारी चीनी मिलों, जिला यूनियनों और बहुराज्य सहकारी समितियों के आंकड़े एकत्रित/मैप किए गए। तीसरे चरण में अन्य बाकी क्षेत्रों में सभी 8 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों के डेटा की मैपिंग की गई।

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD